एक त्यागी समिति बनाई गई थी और उस से काफी फल निकला था तो मैं जानना चाहता हूं कि अब जो टैक्सों के वसूल करने में टाल-मटोल हो रही है क्या उस के लिये कोई उपाय सोचा जा रहा है ?

Mr. Speaker: Next Question.

Shri M. L. Dwivedi: What happened to my question?

Mr. Speaker: It does not call for any answer.

Shri Hem Barua: Though so many supplementaries are put, somehow we are still left in the dark.

Mr. Speaker: Hon. Members can find out other avenues of having them discussed in more detail.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order, there has not been merely evasion of tax, but evasion of answers also.

Shri Tyagi: It is avoidance but evasion: avoidance is legal.

श्री बड़े : आन ए प्वायंट आर्डर, सर । आनरेबल मेम्बर ने प्रश्न पूछा और मिनिस्टर साहब चुप बैठे रहे । इस के बाद माननीय अध्यक्ष ने अगला प्रश्न पूछने के लिये कहा । माननीय अध्यक्ष या तो इनसिस्ट करते कि मिनिस्टर साहब को क्या कहना है, या वह हाउस को बताते कि इस प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है । चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इस लिये हम सब चुप चाप बैठे रहे कि शायद माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बद-किस्मती यह है कि मैं ने जो वह कहा कि इस के आन्सर की जरूरत नहीं है, उस को मानीय सदस्य ने सुना नहीं और अब वह मुझ को सलाह दे रहे हैं ।

I have already said that, but the hon. Member did not listen to my observation.

श्री बड़े: मैं ने वह सुना, लेकिन जब मंत्री महोदय बैठे रहे, तो माननीय अध्यक्ष ने अगला क्वेस्चन काल किया । उस के बाद जब माननीय सदस्य उठे, तो आप ने कहा कि इस का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं चाहता, तो मैं उस वक्त जरूर जोर देता कि इस का जवाब दिया जाये, लेकिन मैं ने कहा कि इस की जरूरत नहीं है । इसी लिये मैं अगले क्वेस्चन पर चला गया ।

Mining Leases in Orissa

*91. **Shri Surendranath Dwivedy:** Wil lthe Minister of **Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether any request was made by the Government of Orissa for enhancement of royalties of mining leases in the State; and

(b) what has been the reaction of the Government of India to such a request and whether the desirability of revising the old rates specially in regard to iron ore mines has been considered for the country as a whole?

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): (a) and (b). The examination of the question of revising the existing rates of royalty, not only with regard to iron-ore but all major minerals as a whole, has already been initiated by the Central Government. Suggestions of all the State Governments have been obtained. In respect of iron-ore, the Government of Orissa originally had not recommended any increase but, subsequently, made such a recommendation. Their suggestions, along with the suggestions received from other quarters concerned, are under final examination; the decisions to be taken will be applicable to the country as a whole.

Shri Surendranath Dwivedy: Is it a fact—as the hon. Minister says—that the Government of Orissa demanded an increase of royalties, or a reduction in the rate of royalties was suggested?

Shri K. D. Malaviya: So far as the increase in the rate of royalities of iron is concerned, previously the Government of Orissa did not propose any increase in the royalties. They wanted it to stay where it was. Subsequently—quite recently—when the new Government was formed, there was a proposal from the Government of Orissa for an enhancement of royalties on iron ore. That, along with the other proposals of State Governments, is under examination.

Shri Surendranath Dwivedy: Is it a fact that some of the leasees are in arrears and they have requested the Government of India to remit those arrears?

Shri K. D. Malaviya: We have no official information with regard to accumulation of arrears anywhere, but off and on, I read in newspapers and also in some letters addressed to me that certain arrears are accumulating which is being disputed by one party or another. Therefore, we cannot say anything one way or the other.

Shri Vidya Charan Shukla: Is it a fact that the Government of Orissa and other State Governments have asked for profit-sharing in the mining projects undertaken by the Central Government, and if so, whether Government have considered this request of the State Governments?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्वैश्चन के दौरान में कोई मिनिस्टर या व्हिप इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, जिस तरह से उधर वे कर रहे हैं ।

Mr. Speaker: Order, order. Even though I realize that the Whips have got some delicate jobs to perform and they often have to go round, even then they are subject to discipline and they should observe the rules of procedure. They should not be found standing in the passages and having consultations with each other.

Shri K. D. Malaviya: Sir, the supplementary which has been asked does not relate to this question of royalty, it is a general question.

पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

*६२. **श्री वाल्मीकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिगणित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये मिलने वाली छात्रवृत्तियों के राज्य सरकारों के हाथ में जाने से उन छात्रों को छात्रवृत्तियों के भुगतान में देर होने के कारण, कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ताकि यह कार्य केन्द्र सरकार के हाथ में आ जाये ?

शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

I shall read the answer in English also.

(a) No, Sir.

(b). Does not arise.

श्री वाल्मीकी : अब तक के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि न केवल मेरे अपने राज्य में बल्कि अनेक अन्य राज्यों में भी जिन की मुझे जानकारी है, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का जो काम राज्य सरकारों को दे दिया गया है, उससे इनके वितरण में देरी तो होती ही है, उसके साथ ही साथ उनका वितरण भी सही आधार पर नहीं होता है । अनेक विद्यार्थियों को इस देरी के कारण पहले ही अपनी स्टडी छोड़ देनी पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की शिकायतें माननीय मंत्री जी की जानकारी में आई हैं ?